



शिक्षा क्षेत्र में सुधार

यह एडिटरियल 12/10/2022 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "India@75 looking at 100: What India's education system needs" लेख पर आधारित है। इसमें भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधारों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

वर्ष 2030 तक भारत में विश्व में सर्वाधिक युवा आबादी होगी। युवा आबादी का यह विशाल आकार तभी वरदान सिद्ध होगा जब ये युवा कार्यबल में शामिल होने के लिये पर्याप्त कुशल होंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगी।

- लेकिन शिक्षा की वर्तमान स्थिति उपयुक्त अवसंरचना की कमी, शिक्षा पर नमिन सरकारी व्यय (जीडीपी के 3.5% से कम) और छात्र-शिक्षक अनुपात की वषिमता (एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात प्राथमिक विद्यालयों के लिये 24:1 है) जैसी प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रही है।
- इस प्रकार यह उपयुक्त समय है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जाए और ऐसा आधुनिक शिक्षण दृष्टिकोण अपनाया जाए जो उत्तरदायी एवं प्रासंगिक हो। इसके अलावा, [राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020](#) (National Education Policy- NEP 2020) के उद्देश्यों को भी साकार किया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएँ

- NEP 2020 का उद्देश्य "भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति" बनाना है। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के बाद से भारत में शिक्षा के ढाँचे में सुधार के अधिक प्रयास नहीं हुए हैं और यह इस क्रम में केवल तीसरा बड़ा सुधार ही है।
 - इससे पूर्व की दो शिक्षा नीतियाँ वर्ष 1968 और 1986 में लाई गई थीं।
- इसका उद्देश्य एक खुली स्कूली शिक्षा प्रणाली के माध्यम से 2 करोड़ स्कूली बच्चों को पुनः मुख्यधारा में वापस लाना है।
- मान्यता के एक नए ढाँचे और सार्वजनिक एवं निजी दोनों तरह के स्कूलों को वनियमिति करने हेतु एक स्वतंत्र प्राधिकरण के साथ विद्यालयों का प्रशासन अब रूपांतरित हो जाएगा।
- 360-डिग्री समग्र प्रगति कार्ड के साथ मूल्यांकन के तरीके में सुधार किया जाएगा और लर्निंग आउटकम की प्राप्ति के लिये छात्र प्रगति पर नज़र रखी जाएगी।
 - इंटरनेट के साथ व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से शुरू होगी।

शैक्षिक सुधारों से संबंधित अन्य प्रमुख सरकारी पहलें:

- प्रौद्योगिकी वर्द्धन शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme on Technology Enhanced Learning)
- [सर्व शिक्षा अभियान \(SSA\)](#)
- प्रज्ञाता (PRAGYATA)
- [मध्याह्न भोजन योजना](#)
- [बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ](#)
- [पीएम शरी स्कूल \(PM SHRI Schools\)](#)

भारत में शिक्षा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख समस्याएँ

- स्कूलों में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (UDISE), 2019-20 के अनुसार, केवल 12% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा और केवल 30% में कंप्यूटर उपलब्ध हैं।
 - इनमें से लगभग 42% स्कूलों में फर्नीचर की कमी थी, 23% में बजली की कमी थी, 22% में शारीरिक रूप से निश्चित के लिये रैंप की कमी थी और 15% में जल, सफाई एवं स्वच्छता (Water, Sanitation and Hygiene-WASH) सुविधाओं की कमी थी।

- **उच्च 'ड्रॉपआउट' दर:** प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर वदियालय छोड़ने की दर (dropout rate) बहुत अधिक है। 6-14 आयु वर्ग के अधिकांश छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं। इससे वृत्तीय और मानव संसाधनों की बर्बादी की स्थिति बनती है।
 - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, 2019-20 स्कूल वर्ष से पहले 6 से 17 आयु वर्ग की 21.4% बालिकाओं और 35.7% बालकों स्कूल छोड़ने के पीछे का मुख्य कारण पढ़ाई में रुचि का न होना बताया।
- **'ब्रेन ड्रेन' की समस्या:** IIT और IIM जैसे शीर्ष संस्थानों में प्रवेश पाने के लिये कड़ी प्रतस्पर्द्धा के कारण भारत में बड़ी संख्या में छात्रों के लिये एक चुनौतीपूर्ण शैक्षणिक वातावरण का निर्माण किया गया है। इससे फरि वे शिक्षा के लिये वदिश जाना पसंद करते हैं, जिससे देश अच्छी प्रतस्पर्द्धा से वंचित हो जाता है।
 - भारत में नशिचति रूप से शिक्षा का मात्रात्मक वस्तिार हुआ है लेकिन गुणात्मक मोरचे पर (जो किसी छात्र के नौकरी पाने के लिये आवश्यक है) यह पछिड़ा हुआ है।
- **बड़े पैमाने पर नरिक्षरता:** शिक्षा के संवरद्धन पर लक्षति संवेधानिक निरदेशों और प्रयासों के बावजूद लगभग 25% भारतीय अभी भी नरिक्षर हैं, जो उन्हें सामाजिक और डिजिटल रूप से भी वंचित करता है।
- **भारतीय भाषाओं पर पर्याप्त ध्यान का अभाव:** भारतीय भाषाएँ अभी भी अवकिसति अवस्था में हैं, वशिष रूप से वजिज्ञान वषियों में शिक्षा का माध्यम अंगरेज़ी है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण छात्रों के लिये असमान अवसर की स्थिति बनती है।
 - इसके साथ ही, भारतीय भाषाओं में मानक प्रकाशन उपलब्ध नहीं हैं।
- **तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का अभाव:** हमारी शिक्षा प्रणाली मुख्यतः सामान्यज्ञ प्रकृतिकी है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का विकास पर्याप्त असंतोषजनक है, जिसके कारण शक्ति बेरोज़गारों की संख्या दनि-ब-दनि बढ़ती जा रही है।
- **वहनीयता/सामर्थ्य:** ग्रामीण स्तर पर नमिन आय के कारण शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। जागरूकता एवं वृत्तीय स्थरिता की कमी के कारण कई माता-पति शिक्षा को नविश के बजाय खरच के रूप में देखते हैं। वे बच्चों को शिक्षा दलाने के बजाय चाहते हैं कि उनके बच्चे काम करें और पैसे कमाएँ।
 - उच्च शिक्षा के मामले में, आसपास अच्छे संस्थानों की कमी छात्रों को शहरों का रुख करने के लिये वविश करती है, जिससे अभिवाकों का खरच बढ़ जाता है। सामर्थ्य की इस समस्या के कारण नामांकन की नमिन दर जैसा परिणाम प्राप्त होता है।
- **लगि-असमानता:** समाज में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिये शिक्षा के अवसर की समानता सुनशिचति करने के सरकार के प्रयासों के बावजूद भारत में महिलाओं की साक्षरता दर, वशिष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी बदतर है।
 - **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF)** के अनुसार, गरीबी और स्थानीय सांस्कृतिक कुप्रथाएँ (कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और कम उम्र में वविह) पूरे भारत में शिक्षा क्षेत्र में लैगिक असमानता के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं।
 - शिक्षा में एक और बाधा देश भर के स्कूलों में व्याप्त स्वच्छता की कमी भी उत्पन्न करती है।

आगे की राह

- **अनुभवात्मक अधगम दृष्टिकोण की ओर:** छात्रों को व्यावहारिक लरनिग अनुभव प्रदान करने के लिये और कार्यबल में प्रवेश के समय उन्हें बाहरी दुनिया का सामना करने हेतु तैयार करने के लिये समस्या-समाधान और नरिणय लेने से संबंधित वषियों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने की आवश्यकता है।
 - अनुभवात्मक अधगम (Experiential Learning) प्रत्येक छात्र से सक्रिय भागीदारी सुनशिचति करा सकने की अपनी क्षमता से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है, जो बदले में उनकी संवेगात्मक बुद्धिमत्ता (emotional intelligence) को प्रेरति करता है और उन्हें आत्म-शिक्षण (self-learning) के मार्ग पर आगे बढ़ाता है।
 - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को शैक्षिक क्षेत्र से संबद्ध करने से भी अनुभवात्मक अधगम को बल मलिया।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन:** NEP के कार्यान्वयन से शिक्षा प्रणाली को उसकी नींद से जगाने में मदद मलि सकती है।
 - वर्तमान 10+2 प्रणाली से हटकर एक 5+3+3+4 प्रणाली की ओर आगे बढ़ने से प्री-स्कूल आयु वर्ग औपचारिक रूप से शिक्षा व्यवस्था में शामिल हो जाएगा।
- **शिक्षा-रोज़गार गलियारा:** भारत की शैक्षिक व्यवस्था को व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करने और स्कूल (वशिषकर सरकारी स्कूलों में) में सही मार्गदर्शन प्रदान करने के माध्यम से संवरद्धति करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनशिचति हो सके कि छात्रों को शुरू से ही सही दशिा में नरिदेशति कया जा रहा है और वे करियर के अवसरों से अवगत हैं।
 - ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों में भी व्यापक संभावनाएँ मौजूद हैं और वे अध्ययन के प्रतस्पर्द्धा भी होते हैं, लेकिन उनके पास सही मार्गदर्शन की कमी होती है। यह न केवल बच्चों के लिये बल्कि उनके माता-पति के लिये भी आवश्यक है जो एक तरह से शिक्षा में लगि अंतर को कम करेगा।
- **भाषाई अवरोध को कम करना:** अंगरेज़ी को अंतरराष्ट्रीय समझ के लिये शिक्षा (Education for International Understanding- EIU) के साधन के रूप में रखते हुए, अन्य भारतीय भाषाओं को समान महत्त्व देना महत्त्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से वभिनिन भाषाओं में संसाधनों का अनुवाद करने के लिये वशिष प्रकाशन एजेंसियों की स्थापना की जा सकती है ताकि सभी भारतीय छात्रों के पास उनकी भाषाई पृष्ठभूमि से अपरभावति एकसमान अवसर उपलब्ध हो।
- **अतीत से भवषिय की ओर:** भवषिय की ओर देखना महत्त्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही हमें अपनी गहरी जड़ों को भी मन में बनाए रखना चाहिये।
 - प्राचीन भारत की 'गुरुकुल' प्रणाली से बहुत कुछ सीखा जा सकता है जो सदयियों पहले अकादमिक शिक्षा के बजाय समग्र विकास (जो आज आधुनिक शिक्षा का एक वचिरार्थ वषिय बना है) पर केंद्रति थी।
 - प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में नैतिकता एवं मूल्यपरक शिक्षा अधगम या लरनिग के मूल में रही थी। आत्मनरिभरता, समानुभूति, रचनात्मकता और अखंडता जैसे मूल्य प्राचीन भारत में महत्त्वपूर्ण रहे थे जो आज भी प्रासंगिक हैं।
 - प्राचीन काल में शिक्षा मूल्यांकन वषियगत ज्ञान के वरगीकरण तक ही सीमति नहीं था। छात्रों का उनके द्वारा सीखे गए कौशल और वास्तविक जीवन स्थितियों में व्यावहारिक ज्ञान को आजमा सकने की क्षमता के आधार पर मूल्यांकन कया जाता था।
 - आधुनिक शिक्षा प्रणाली को भी मूल्यांकन की ऐसी ही एक प्रणाली तैयार करनी चाहिये।

